

**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1107**  
**27 दिसंबर, 2017 को उत्तर के लिए**

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अधिशेष भूमि पर  
नए इस्पात संयंत्र**

**1107. श्रीमती विजिला सत्यानंत:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार 2030 तक इस्पात उत्पादन क्षमता को दुगुना कर 300 मिलियन टन करने में सहायता करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि पर नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान में इस्पात उत्पादन क्षमता 126 मिलियन टन है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि 5000 करोड़ रुपये वाले ऑटो ग्रेड इस्पात संयंत्र का निर्माण करने के लिए एसएआईएल (सेल) द्वारा एक निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उपक्रम को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जा सकता है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री**

**(श्री विष्णु देव साय)**

(क): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख): मार्च, 2017 की स्थितिनुसार, भारत की कूड क्षमता 128.28 मिलियन टन है।

(ग) और (घ): सेल के निदेशक बोर्ड ने स्वचालित इस्पात व्यापार हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए आर्सेलर मित्तल एस.ए. के साथ शर्तों के एक विवरण पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के अंतर्गत भारत में लगभग 1.5 एमटीपीए क्षमता की एक आधुनिक कोल्ड-रोलिंग मिल और डाउनस्ट्रीम फिनिशिंग सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जिनसे स्वचालित क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उन्नत इस्पात के उत्पाद उपलब्ध होंगे।

\*\*\*\*\*